International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 04(II), October - December, 2021, pp.156-160

महिलाओं के उघमिता विकास में उघमिता विकास कार्यक्रमों के योगदान का अध्ययन करना (इन्दौर संभाग के विशेष संदर्भ में)

लखन लाल चौकसे*

सार

किसी भी राष्ट् के विकास के लिए उधमिता अतिआवश्यक तत्व है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कोई भी देश उपलब्ध मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके ही आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चूकिं मानव का आधा भाग महिलायें होती है। इसलिए कोई राष्ट् महिलाओं की सहभागिता के बिना आर्थिक विकास का सपना पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट् में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहित करने में महिलाओं की भूमिका बडती जा रही है। जहां तक भारत का प्रश्न है यहां पर आदिकाल से महिलाऐं उपेक्षित रहीं है। उनका कार्यक्रम का दायरा घर परिवार तक सीमित रहा है। सत्यता यह है कि महिलाओं के अपने घर परिवार तक सीमित रहने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। आज उधमिता के क्षेत्र महिलाएं प्रबंधन,संचालन व सहभागिता के क्षेत्र में तीव्र गति से सबलता प्राप्त कर रही है। भारत की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं का स्थान एवं कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक सीमित है, किन्तु आदिकाल से ही वह पुरुषों से आवश्यकता पडने पर पीछे नही रही। विकसित देशों में महिलायें पुरुषों से आवश्यकता पडने पर पीछे नही रही । विकसित देशों में महिलायें पुरुषों के साथ बिना भेदभाव के कार्य करती रहती है , जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्रयासरत है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश जैसे जैसे महिलाओं में विकसित हो रहा है। क्रमशः कृषि, पशुपालन के अतिरिक्त औघोगिक एवं तृतीयक क्षेत्रों मे भी महिला श्रमिको की भागीदारी बडी है। क्या महिलाओं में उधमिता का पर्याप्त विकास हो रहा है। इस शोध पत्र में महिलाओं के उधमिता विकास का अध्ययन किया गया है। समस्त अध्ययन के लिए इन्दौर संभाग का संदर्भ लिया गया है।।

शब्दकोशः *महिला उधमिता, उधमिता विकास, उधमिता विकास कार्यक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था।*

प्रस्तावना

उघमिता आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल मंत्र है। उघमिता से बाहर और उघमिता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उघमिता मानव की सभी क्रियाओं में व्याप्त है उघमिता ही वह संसाधन है जो संगठनों को उत्पादक,उद्देश्यपूर्ण एवं कार्यशील बनाता है। प्रबंध विशेषज्ञ पीटर ड्कर लिखते है एक आवश्यक विशिष्ट एवं प्रमुख संस्था के रुप में उघमिता का प्रादुर्भाव समाज के इतिहास में एक केन्द्रीय घटना है। इस शताब्दी के संक्राति काल से ही कोई एक नयी संस्था,एक नया प्रभुत्व समूह इतनी तेजी से नही उभरा है जितना की उघमिता भूमण्डलीकरण, आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के बाद सभी समाजों में उघमिता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रुप में केन्द्रीय तत्व बनकर उभरा है क्यों कि उघमिता के द्वारा ही हम गरीबी बेरोजगारी व निम्न जीवन स्तर आदि समस्याओं से छुटकारा पा सकते है। उघमिता के क्षेत्र में लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा है तथा आज भी काफी सीमा तक विघमान है। विगत तीन दशकों में हुए सामाजिक , आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों के फलस्वरुप उघमिता के क्षेत्र में महिलाओं का आगमन हुआ है। महिला उघमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एवं निजी संस्थान विशेष रुप से प्रयत्नशील है। उघमिता विकास कार्यक्रम को संगठित एवं विकसित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई संस्थानों की स्थापना की गई है।

---

[6] शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविघालय, उज्जैन, म.प्र.।

केन्द्र सरकार की उघमिता प्रोत्साहन के लिए भारतीय उघमिता विकास संस्थान अहमदाबाद लिमिटेड राष्ट्रीय लघु उघोग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान , राष्ट्रीय उघमिता विकास मंडल , अखिल भारतीय लघु बोर्ड आदि संस्थाएँ कार्यरत है। मध्यप्रदेश सरकार की उघमिता को बढावा देने के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड म.प्र.खादी एवं ग्रामोघोग बोर्ड ,जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र म.प्र.कन्सलटेन्सी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, उघमिता विकास केन्द्र म.प्र आदि संस्थाएँ कार्यरत है।

इन संस्थानों द्वारा उघमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय तकनीकी तथा प्रबंधकीय पहलुओं से संबंधित ज्ञान को प्रशिक्षणार्थियों तक पहुँचाया जाता है। इसके साथ –साथ उघमियों को बाह्रय अवसरों, सहायताओं तथा सामाजिक एवं संगठनात्मक सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है ।

इस शोध पत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उघमिता विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के उघमिता विकास का अध्ययन किया गया है। विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत – उघमिता विकास केन्द्र म.प्र.,जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र को शामिल किया गया है। समस्त अध्ययन के लिए इन्दौर संभाग का संदर्भ लिया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा

- इंदिरा मिश्र (2000) ने गरीब महिलाऐं एवं रोजगार पुस्तक में सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं तथा महिलाओं को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को बताया गया है। महिलाओं द्वारा सरकारी नीतियों के सही उपयोग तथा आर्थिक सशक्तीकरण के साथ महिलाओं के सुखद भविष्य का वर्णन भी किया है।
- शीला वर्मा (2011) में विकास कार्यक्रमों में जनजातीय महिलाओं पर योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन शोध पत्र में जनजातीय महिलाओं पर विभिन्न योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन कर बताया गया कि महिलाओं में आर्थिक विकास एवं सशक्तीकरण के लिए स्वयं की आवश्यकता तथा प्रयासों की आवश्यकता है।

उद्देश्य

स्वाधीनता के 70 वर्ष बीत जाने पर भी महिला उघमिता का विकास वांछित तीव्रता से नही हुआ है इस कमी का क्या कारण है? अतीत में हुई कमियों का पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए? इस शोधपत्र में महिला के उघमिता विकास में महिला उघमिता कार्यक्रमों के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय राज्य एवं ग्राम स्तर पर महिला उघमिता के उन्नयन तथा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, एवं संस्थापक अवरोधों को पार करने के लिए इस क्षेत्र में निरंतर शोध की आवश्यकता है।

- महिला स्वरोजगार मूलकयोजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना।
- महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं में समस्याओं के सुधार हेतु उचित सुझाव देना।
- महिला उघमिता विकास कार्यक्रमों हेतू सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदानों की व्याख्या करना।

महिला उघमियों की क्षमता,दक्षता, तथा गुणों का विकास करने उनकी व्यावसायिक श्रृंखला को मजबूत करने हेतू सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा बनाई गई योजनाओं का अध्ययन करना।

उपकल्पना

- महिलाओं की शिक्षा का विस्तार होने से उघमिता के प्रति जागरुकता आयी है।
- महिलायें अपने अधिकारें और कर्तव्यों के प्रति सजग हुई है और समाज में उघमिता के जरिये विशिष्ट स्थान बनाने की ललक उनमें पैदा हुई है।
- संभाग में महिला उघमी मनोवृति का अभाव है।
- महिलाओं उघमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाओं की प्राप्ति हेतू कई कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

शोध प्रविधि

शोध कार्य में महिला उघमिता एवं महिला उघमिता के विकास में उघमिता योजनाओं से संबंधित वास्तविक एवं विश्वसनीय ऑकडों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के ऑकडों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक ऑकडें स्वयं स्थल पर जाकर मूल स्त्रोंतो से एकत्र किये गये है। जबकि द्वितीयक ऑकडें महिला उघमिता एवं महिला उघमिता विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित योजनाओं हेतू विभिन्न प्रकाशित– अप्रकाशित पुस्तकों,शोध–पत्र–पत्रिकाओं ,समाचार पत्रों ,शासकीय प्रतिवेदनों आदि से एकल कर प्रयोग किये गये है। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी एवं इन्टरनेट आदि के भी ऑकडें एवंविष्य वस्तु से संबंधित स्टडी मटेरियल एकत्र करने में प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोघ कार्य सही अर्थों में तभी प्रभावी होते है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाये । इसके लिए यह आवश्यक है कि शोघार्थी द्वारा शोघ अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोघ उपकरण द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाये। शोध क्षेत्र में इन्दौर जिले के महिला उघमिता एवं स्वरोजगार मूलक योजनाओं एवं आर्थिक विकास हेतु शोधार्थी ने शोध उपकरणों की सहायता ली है,जिसके द्वारा एकत्रित तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गयी है। जो इस प्रकार है–

इन्दौर जिले में प्रधानमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम की स्थिति

प्रदेश के अन्य जिलों की भॉति इन्दौर जिले में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 से संचालित है। यह वास्तव में 31.03.2008 तक दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मिश्रित स्वरुप है।

सारणी 1: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की लक्ष्य एवं पूर्ति (राशि लाख रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5
2012.13	40	148.20	30	135.91
2013.14	42	158.80	39	162.10
2014.15	35	149.00	30	169.59
2015.16	39	193.10	34	188.19
2016.17	70	191.85	60	143.42
2017.18	74	205.45	62	165.18
योग	300	1046.4	255	964.39

स्त्रोत–जिला व्यापार एवे उघोग केन्द्र इन्दौर (म.प्र)

जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र इन्दौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी विगत पॉच वर्षों के दौरान 300 में 255 हितग्राहियों द्वारा स्वरोजगार संबंधी लघु एवं मध्यम स्तर के उघोगों की स्थापना जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र इन्दौर के माध्यम से स्थापित कर चुके है। जिनमें से 964.39 लाख रुपये की आर्थिक मदद् बैंकों के माध्यम से प्रदाय की जा चुकी है। विगत पॉच वर्षों की लक्ष्य प्राप्ति को यदि देखा जाये तो अभी तक निर्धारित भौतिक लक्ष्यों में से 65.92 प्रतिशत औसत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार वित्तीय प्रतिपूर्ति की लक्ष्य 95.03 रहा है।

दीन दयाल रेाजगार योजना

योजना का उद्देश्य

उघोग सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाइयों/गतिविधयों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंको/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवे मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रुप में देना।

वर्ष		लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)	भौतिक	वित्तीय(रु.लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2012.13	181	28.72	52	28.72
2.	2013.14	160	6.89	70	6.89
3.	2014.15	84	7.80	84	7.80
4.	2015.16	84	4.97	80	7.97
5.	2016.17	70	2.43	31	2.43
	2017.18	62	2.15	29	1.96
	योग	641	52.96	346	52.77

प्राप्त पॉच वर्षों के ऑकडों से स्पष्ट है कि शासन को चाहिए कि महिला उघमिता ज्यादा से ज्यादा सशक्त द्वारा जिले में रखे गयें 64 भौतिक लक्ष्य में से मात्र हो,क्यों कि महिला उघमिता के सशक्त होने से अपने 346 भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है, जबकि आप ही की कई समस्यायें कम हो जायेगी। वित्तीय लक्ष्य एवं पूर्ति पूरे 52.77 लाख रुपये ही है।

महिला उघमियों की समस्यायें

- देश का सामाजिक ढॉचा परम्परागत एवं महिला उघमियों के प्रति कठोर संवेदनहीन है।
- सामान्यतः महिलाओं में अपने आप निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है।
- भारतीय महिला उघमियों की प्रमुख समस्या भारतीय पुरुषों की दोहरी मानसिकता है।
- पुरुष श्रमिकों एवं कर्मचारियों के साथ काम न कर पाना।
- महिला उघमी कभी–कभी नवीनतम तकनीक से पूर्णतः जानकारी नहीं ले पाती है। जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है।
- भारत में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पुरुष की तुलना में कम है शिक्षा के अभाव में यह तकनीकी ज्ञान एवं विपणन के सम्बन्ध में सजग नहीं रह पाती जिसका विपरीत प्रभाव उनके व्यवसाय के विकास पर पडता है।
- महिला उघमियों को सामान्यतः ऋण की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

सुझाव

किसी भी योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतू बेहतर प्रबंध का होना अत्यंत आवश्यक है प्रबंधकीय नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग मानव संसाधन होता है अपने शोध के दौरान मैंने पाया कि शासन की योजनाओं को यथार्थ रुप में परिणित करने का दायित्व जिला पंचायत का अत्यधिक कार्य होता है अंतः शासन को यह पहल करना

- महिला उघमियों की समस्याओं के समाधान के लिए महिला सशक्तीकरण के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- महिला उघमिता को प्रोत्साहित करने के लिये औघोगिक परिवेश को बदलना होगा। साथ ही महिला उघमियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें देनी चाहिए तथा कुछ विशिष्ट उघोगों को महिला उघमियों के लिये आरक्षित कर देना चाहिए।
- महिला उघमियों को कम ब्याज दर शाख सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- महिला उघमियों को श्रेष्ठ प्रबन्धक बनाने के लिए प्रबन्धकीय शिक्षा आवश्यक है। अतः महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

आज देश के समक्ष सबसे बडी चुनौती बेरोजगारी की है। प्रत्येक पढा लिखा युवक/युवतियों का उद्देश्य शिक्षा पश्चात रोजगार प्राप्त करना होता है। देश के प्रत्येक शिक्षित वर्ग को शासकीय नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसका प्रमुख कारण है शासकीय पदों का सीमित होना। ऐसी स्थिति में देश में स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त हो सकें ।

भारत का वास्तविक आर्थिक विकास ग्रामीण विकास पर आधारित है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय ग्रामों के सर्वागीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक विकास कार्यक्रम अपनाये गये है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम , मध्यप्रदेश व स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अतिरिक्त स्वरोजगार प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,दीनदयाल रोजगार योजना व मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग स्वरोजगार योजना को शोध प्रबंध का विषय बनाया गया और शोध प्रबंध को उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय प्रबंध व रोजगार दो भागों मे विभक्त कर परिणाम प्राप्त किया गया है।

हमारे देश की चार राज्यों की मुख्यमंत्री भी महिला है। व्यापार ,व्यवसाय,बैंक आदि बडी–बडी संस्थाओं मे महिलाओं की संख्या बडती जा रही है। महिला उघमी बनकर आत्मनिर्भर एवं देश के विकास में पुरुषों के बराबर सहभागी बन रहीं है। महिला उघमियों के लिए सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक दृष्टिकोण से बडे बदलाव की सोच रखनी चाहिए। उनको समानता का अधिकार केवल संविधान में न होकर व्यावहारिक भी होनी चाहिए तभी महिला उघमी स्वतंत्र रुप से कार्य कर सकती है और अपने परिवार व देश के विकास में भागीदारी निभा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एस.के.मिश्रा बी.के.पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिसिंग हाउस 2007
2. सिंह बी.राजेन्द्र ग्रामों का आर्थिक पुनरुधार, साहित्य सम्मेलन प्रयोग 1930
3. सिंह व निगम, भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र, नवयुग साहित्य सदन आगरा 1971.72
4. दन्त सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चन्द्र एवं क्र. न्यू दिल्ली 2009
5. शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश, रिसर्च मैथोलॉथी,पंचशील प्रकाशन जयपुर 2004
6. आर.ए. दुबे, आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल पब्लिशर्स हाउस नई दिल्ली,2006
7. जैन,डॉ. एम.के शोध विधार्थी यूनीवसिटी पब्किेशन नई दिल्ली,2006
8. डॉ चतुर्भुज मंमोरिया भारत का आर्थिक समस्यायें साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर 2007.08
9. डॉ. अग्रवाल के.बी– उघमिता विकास।
10. प्रसाद भगवान– इंटरप्राइजेज फार वूमेन सोशल वेलफेयर।
11. डॉ. तिवारी अंशुल,डॉ. तिवारी संजय – महिला उघमिता,ओमेगा पब्लिकेशन्स दिल्ली।
12. उघमिता समाचार पत्र।
13. मध्य प्रदेश संदेश।
14. जिला उघोग केन्द्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इन्दौर (म.प्र)
15. दैनिक समाचार, दैनिक भास्कर, राज एक्सप्रेस, पत्रिका।
16. डॉ. जैन एवं शर्मा(2011) उघमिता के मूलाधार, रमेश बुक डिपो, जयपुर
17. डॉ. गंगेले एवं जैन (2009), उघमिता विकास,म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
18. इंदिरा मिश्र (2000), गरीब महिलायें एवं रोजगार (पुस्तक)
19. शीला वर्मा (2011), विकास कार्यक्रमों में जनजातीय महिलाओं पर योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन(शोध पत्र)
20. उघमिता समाचार पत्र, उघमिता विकास केन्द्र म.प्र. भोपाल
21. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उघमिता विकास केन्द्र म.प्र.भोपाल

❖◆❖